साप्ताहिक
युवा प्रदेश
Freedom Of Speech
RNI. NO. MPHIN/2015/76299
संपादक-नागेश नरवरिया
YP24 NEWS
जिले एवं तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है संपर्क करें...
संपर्क करे- 9425156055
वर्ष-10 अंक-22 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 10 जुलाई 2026 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ-08 मूल्य 2 रूपये

प्रेस एवं पत्रकार को स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से मिला, जानिए - Lagal general knowledge

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाली प्रेस को किसी भी भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध, सरकार की मनमानी के विरुद्ध प्रकाशन करने का एवं लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध प्रकाशित करने का कानूनी अधिकार प्रारंभ से ही है या कही से मिला है, जानिए इसके पीछे का राज।

लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

एक छोटी सी कहानी:-

आटोशंकर नामक व्यक्ति जो तमिलनाडु राज्य का रहने वाला था उसे हत्या के आरोप में चेगलेपुट उपजेल में बंद करके रखा था। उसने जेल में ही 350 पृष्ठों वाली अपनी एक आत्मकथा लिखी और अपनी पत्नी के द्वारा वकील भेजा उसे प्रकाशित के लिए। उसने अपनी जीवनी में लिखा कि उसके द्वारा किए गए अपराधों में राज्य के एएसआई, आईपीएस और अन्य अधिकारियों से उसके संबंध थे एवं कई अधिकारी उसके साथ अपराध में सहभागी भी थे। इसकी पुष्टि के लिए आटोशंकर के घर पर पार्टी की एक वीडियो से भी हुई थी, लेकिन इस जीवनी को प्रकाशित करने पर तमिलनाडु सरकार ने रोक लगा दी। इसके विरोध में पत्रिका संपादक रामगोपाल ने तमिल सरकार के आदेश को निरस्त करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी।

जानिए प्रेस की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण निर्णय

राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (निर्णय वर्ष 1994)ः- मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश मे ऐसा कोई कानून नहीं है जो सरकार को उसके अधिकारियों के बदनाम करने वाली सामग्री के प्रकाशन से पहले ही रोक लगा दे। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि प्रकाशन सामग्री अदालत के अभिलेख समेत किसी भी लोक अभिलेख पर आधारित होती हो तो उसके किसी भी पहलू के प्रकाशन का विरोध नहीं किया जा सकता है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि सरकार, स्थानीय अधिकारी और अन्य अंग और संस्थाएं जो भी सरकारी शक्ति का उपयोग करते हैं वे मानहानि के लिए नुकसानी का वाद दायर नहीं कर सकते है। किन्तु अगर किसी अधिकारी, व्यक्ति या महिलाओं की निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है जैसे कि एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी के अलावा अपनी पत्नी, अपने परिवार की शादी, प्रजनन, माँ बनने और शिक्षा की गोपनीयता बजाए रखने का निजिता का अधिकार है एवं साथ ही किसी बलात्कार की शिकार महिला, योन हिंसा, अपहरण या इसी प्रकार के अन्य संगीन अपराध से पीड़ित महिलाओं का नाम प्रकाशित नही किया जा सकता है। राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (निर्णय वर्ष 1994) अतः सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पत्रिका संपादक रामगोपाल के पक्ष में सुनाते हुए कहा कि आटोशंकर की जीवनी को जैसा कि वह लोक अभिलेख से प्रतीत होती है उसे उसकी सहमति के बिना भी प्रकाशित करना प्रेस का मौलिक अधिकार है, किन्तु अगर प्रकाशनकर्ता उसकी निजिता की जानकारी प्राकशित करते हैं तो यह एकान्तता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा इस पर रोक लगाई जा सकती है।

नोटः- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक और महत्वपूर्ण अधिकार दिया है। अगर कोई बात किसी सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके कर्तव्यों के निवार्ह के दौरान किये गए कार्यो तथा दायित्व के उल्लंघन पर प्रकाशित हुई है, तो सरकारी अधिकारी इसमे नुकसानी प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है बस उसे साबित करना होगा की प्रकाशित खबर झूठी एवं असत्य हैं, प्रेस को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है जो कुछ उसने लिखा है वह सत्य है। ÷इसी मामले को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार पर एक ऐतिहासिक मामला आज भी माना जाता है।÷

कृषि और कृषक कल्याण है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

किसानों को सिंचाई के लिए दिन में ही मिलने लगेगी पर्याप्त बिजली

भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आधारभूत विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में %कृषि और कृषक% सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 55 लाख हैक्टेयर से अधिक पहुंच गया है, जिससे कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील में आयोजित किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 30.86 करोड़ रुपए के 12 विकास कार्यो का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इनमें 01 करोड़ 45 लाख 56 हजार रूपये की लागत के 04 कार्यो का भूमि पूजन और 29 करोड़ 39 लाख 92 हजार रूपये लागत के 8 कार्यो का लोकार्पण शामिल है। सम्मेलन में किसान भाइयों ने भावांतर भुगतान योजना एवं केसीसी ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का गजमाला से साथ ही हल भेंटकर एवं महिला किसानों ने राखी बांधकर स्वागत एवं अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हितग्राहियों को हितलाभ वितरण कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परिसर में ÷एक पेड़ माँ के नाम÷ अभियान अंतर्गत पौधा भी लगाया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं उपस्थित अतिथियों ने एक पेड़ माँ के नाम, हर भरा कालापीपल अभियान अंतर्गत 04 लाख पौधे रोपण के लक्ष्य अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी प्रांगण में पौध-रोपण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिकों से अधिक से अधिक पौध-रोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जनभागीदारी से पौध-रोपण अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कालापीपल क्षेत्र 04 लाख पौधे रोपित करने के लक्ष्य का यह वृक्ष गंगा अभियान का नया रिकॉर्ड बना रहा हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि देने तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौपालकों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

सेफ क्लिक 2.0 ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल में साइबर सुरक्षा का महाअभियान, 2000 विद्यार्थियों व शिक्षकों से पुलिस अधीक्षक विदिशा का सीधा संवाद

विदिशा

पुलिस मुख्यालय के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के मार्गदर्शन में संचालित ÷सेफ क्लिक 2.0÷ जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08 जुलाई 2026 को ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल, विदिशा में साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल जागरूकता विषयक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को साइबर अपराधों से बचाव तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में लगभग 2000 विद्यार्थी, शिक्षकगण एवं विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। इस दौरान साइबर अपराधों से संबंधित जागरूकता वीडियो का प्रसारण किया गया, जिससे विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी के नए तरीकों, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक, साइबर बुलिंग, बैंकिंग फ्रॉड एवं सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों की जानकारी तथा उनसे बचाव के व्यावहारिक उपाय समझाए गए। पुलिस अधीक्षक श्री

रोहित काशवानी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल दुनिया में सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उन्होंने अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी, पासवर्ड एवं बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करने तथा सोशल मीडिया पर प्राप्त होने वाले भ्रामक संदेशों से सावधान रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें एवं www.cyber-crime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी ने सरल, व्यावहारिक एवं प्रभावी उदाहरणों के माध्यम से संतोषजनक उत्तर दिया उन्होंने विद्यार्थियों से भविष्य में सदैव डिजिटल रूप से सतर्क रहने तथा अपने परिवार और मित्रों को भी साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने की अपील की।

अमझोर सरपंच पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, जयसिंहनगर थाने में दर्ज हुई NCR

शहडोल।

जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम अमझोर में पट्टे की जमीन पर जोताई को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। इस संबंध में जयसिंहनगर थाना पुलिस ने असंज्ञेय अपराध दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, ग्राम अमझोर निवासी आशा देवी कंवर ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके नाम दर्ज खसरा नंबर 403/1, रकबा 0.450 हेक्टेयर भूमि पर 9 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग 12ः30 बजे ग्राम अमझोर के सरपंच कमलेश सिंह कंवर, ललिता कंवर, श्यामाबाई कंवर एवं श्यामाबाई की छोटी बहू ट्रैक्टर से जोताई करा रहे थे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी पट्टे की भूमि पर जोताई का विरोध किया और ट्रैक्टर चालक से अपने हिस्से की जमीन न जोतने की बात कही, तब सरपंच कमलेश सिंह कंवर ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने का प्रयास किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अन्य आरोपितों ने भी उनका साथ दिया और झूमाझपटी की। हालांकि शिकायतकर्ता के अनुसार घटना में उन्हें कोई स्पष्ट चोट नहीं आई तथा उन्होंने चिकित्सीय परीक्षण कराने से इनकार कर दिया।

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि घटना के दौरान लाला तिवारी एवं संजू कंवर ने बीच-बचाव किया।

जयसिंहनगर थाना पुलिस ने मामले में हृष्टक्रक्रमांक 0986/2026 दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला भूमि विवाद से संबंधित प्रतीत होता है, इसलिए शिकायतकर्ता को आगे की विधिक कार्रवाई के लिए सक्षम न्यायालय में जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर असंज्ञेय अपराध दर्ज कर आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।

रामनगर पुलिस की बड़ी सफलता: विशेष अभियान में तीन गुमशुदा सकुशल मिले, परिजनों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर/रामनगर

जिले में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रामनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस टीम ने लगातार प्रयास और प्रभावी खोजबीन के बाद तीन गुमशुदा व्यक्तियों को सकुशल दस्तयाब कर वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस सफलता से परिवारों ने राहत की सांस ली और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। पुलिस अधीक्षक विक्रांत जी के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगनाथ मारकाम तथा एसडीओपी कोतमा आरती शाक्य के निर्देशन में थाना प्रभारी सुमित कौशिक के नेतृत्व में यह अभियान संचालित किया गया। तलाश अभियान में एएसआई विनोद नाहर एवं आरक्षक मूरत सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई।

पुलिस ने गुम इंसान क्रमांक 13/26 के तहत बरतराई निवासी 27 वर्षीय शंभु केवट, गुम इंसान क्रमांक 16/26 के तहत हरीं निवासी 45 वर्षीय शमनी देवी तथा गुम इंसान क्रमांक 18/26 के तहत सेमरा निवासी 18 वर्षीय महिका केवट को सुरक्षित खोज निकाला। पुलिस ने तीनों गुमशुदाओं को आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अभियान के तहत रामनगर पुलिस लगातार गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश में जुटी है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर परिवारों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

संभागायुक्त की पंडित खुशीलाल चिकित्सा महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति के साथ बैठक संपन्न

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने पंडित खुशीलाल चिकित्सालय परिसर में चिकित्सालय, महाविद्यालय गर्ल्स हॉस्टल ऑडोटोरियम एवं हर्बल गार्डन को जोड़ने के लिए आवश्यक पाथ-वे एवं ब्रिज बनाए जाने की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। संभागायुक्त ने सोमवार को खुशीलाल चिकित्सा महाविद्यालय के सभाकक्ष में महाविद्यालय की कार्यकारिणी समिति की बैठक ली। बैठक में परिसर में बनाए गए हर्बल गार्डन को स्कूल के बच्चों के लिए आयुर्वेदिक पौधों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। विद्यालय अपने छात्र-छात्राओं को अब हर्बल गार्डन का टूर करवा सकते हैं। इसके लिए प्रति छात्र दस रुपए फीस निर्धारण का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय एवं पीजी भवन के रिपेयरिंग कार्य को समय-सीमा में पूर्ण कराए जाने एवं महाविद्यालय में लैब्स के आधुनिकीकरण एवं कार्यप्रणाली को अपग्रेड करने की अनुमति भी दी गई। इसके साथ ही प्रोफेसर्स को समय समय पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस के साथ अन्य प्रोफ़ेशनल की वर्कशॉप आयोजित किए जाने की अनुमति दी गई। सुपर स्पेशिलिटी विंग के लिए आवश्यक दवाइयों को खरीदने की भी अनुमति भी दी गई। संभागायुक्त ने महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में अलग-अलग विभागों में आवश्यक उपकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए सामग्री हेल्थ कॉर्पोरेशन एवं क्रय भंडार नियमानुसार आवश्यक उपकरणों के क्रय करने, डिजिटल एक्स-रे मशीन, अग्निशमन उपकरण, सभी जांच लैब्स में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का अनुमोदन प्रदान किया। महाविद्यालय से संबद्ध पीजी विद्यार्थियों के रिसर्च का पेटेंट करवाए जाने की विस्तृत जानकारी ली और विद्यार्थियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

आज भोपाल में एसएफआई द्वारा एनटीए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया

विरोध प्रदर्शन का संचालन एसएफआई के छात्र नेता दीपक पासवान ने किया। प्रदर्शन का शुरुआती वक्तव्य अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की नेता नीना शर्मा ने अपनी बात रखते हुए दिया। प्रमुख वक्ता के रूप में स्न्रद्ध के जिला संयोजक साथी सोनू ने सभा को संबोधित किया। सीटू के राज्य अध्यक्ष पुषण भट्टाचार्य ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात रखी। भोपाल जिले की जनवादी महिला समिति (जमस) की नेत्री अरुणा सक्सेना ने भी विचार साझा किए। छात्र नेता अमन सिंह चौहान ने भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। मुख्य व आखिरी वक्ता के रूप में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव तेज कुमार टीगा ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आखिरी वक्तव्य दिया। सभा के बाद नेताओं और छात्रों द्वारा एक रैलीद्ध निकाली गई और जिसका समापन अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष किया गया जहाँ पर साथी शुभम मेहरा ने अपने ओजस्वी और जोशीले भाषण के साथ प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए इस विरोध कार्यवाही को समाप्त करने की घोषणा की।

शिक्षक बलीराम अहिरवार जी का एमपीपीएससी में चयन, बने हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर

हल्केवीर सूर्यवंशी, संभागीय संवाददाता

उदयपुरा/रायसेन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024-25 के घोषित परिणाम में श्री बलीराम अहिरवार का हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन हुआ है।

वर्तमान में श्री बलीराम अहिरवार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बीटीआई गाडरवारा में उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-1) के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे वर्ष 2018 से 2021 तक गाडरवारा तहसील में पटवारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नवंबर 2021 में वर्ग-1 शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्यभार संभाला।

अब एमपीपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। उनके शुभचिंतकों, सहकर्मियों एवं सामाजिक जनों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

3 मंजिला मकान से गिरने से सतीश अहिरवार की मौत, परिजनों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर रात भर किया प्रदर्शन। नहीं थे सुरक्षा के इंतजाम मकान मालिक नवनीत रघुवंशी घर से फरार

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा/ रायसेन- नगर की कान्हा सिटी कॉलोनी में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे एक दर्दनाक हादसे में 25 वर्षीय सतीश अहिरवार, पिता कैलाश अहिरवार, निवासी सिलारी कलां, की निर्माण कार्य के दौरान तीन मंजिला मकान से गिरने से मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि हादसा नवनीत रघुवंशी के निर्माणाधीन मकान पर हुआ, जहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। निर्माण कार्य का ठेका भरत अहिरवार के पास था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यदि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था।

मृतक सतीश अपने परिवार का सहारा था। परिवार में एक भाई है, जबकि उसके पिता विकलांग हैं। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हादसे के बाद करीब 200 लोगों की मौजूदगी में मृतक का शव सुबह से लेकर शाम करीब 5 बजे तक घटनास्थल पर रखकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा निर्माण कार्यों में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा परिजनों और ग्रामीणों को समझाइश दी। प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई और सहायता का आश्वासन दिए जाने के बाद स्थिति सामान्य हुई। यह हादसा एक बार फिर निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का तृतीय दिवस सम्पन्न

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार तथा प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज के मार्गदर्शन में शासकीय विधि महाविद्यालय, नर्मदापुरम में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित दीक्षारंभ (प्रवेशोत्सव) समारोह का तृतीय दिवस में विभागाध्यक्ष श्री शिवाकांत मौर्या ने विद्यार्थियों को महाविद्यालय के पुस्तकालय की उपयोगिता एवं उसके प्रभावी उपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पुस्तकालय में उपलब्ध विधिक पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों, जर्नल्स तथा अन्य अध्ययन सामग्री के नियमित अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि विधि शिक्षा में सतत अध्ययन एवं संदर्भ सामग्री का समुचित उपयोग सफलता की आधारशिला है। राजदीप सिंह भदौरिया ने विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की विभिन्न गतिविधियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, व्यक्तित्व विकास एवं रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) एवं इको क्लब की गतिविधियों से विद्यार्थियों को अवगत कराते हुए सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, नेतृत्व क्षमता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों पर अपने प्रश्न एवं जिज्ञासाएँ व्यक्त कीं, जिनका विशेषज्ञों द्वारा संतोषजनक समाधान किया

संपादकीय

भारत माता के लिए जीना और उसके लिए मरना हर भारतीय का दायित्व है

किसी भी सभ्यता का अर्थ है एक विचारशील, विकासशील, उदार और सदाशयी मानव समुदाय। इसलिए सभ्यताएं संघर्ष नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति वफादार बनाती हैं। जो संघर्ष करते हैं, वे सभ्य नहीं, असभ्य कहलाते हैं। इस सामान्य परिभाषा को भारत का अनपढ़ और ग्रामीण समाज भी जानता, समझता है। इसलिए वहाँ यदि कोई झगड़ा करे तो उसे जाहिल यानी असभ्य की संज्ञा दे दी जाती है। सभ्यता की इस भारतीय दृष्टि को सामने रख कर ही इस सभ्यता अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले सभी मानव समुदायों में संवाद के सूत्रों को तलाशना और उन्हें फिर से स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि अत्यंत प्राचीन काल से ही विश्व में एक वैश्विक व्यवस्था विद्यमान थी जो परस्पर संवाद, सहअस्तित्व और सहयोग पर आधारित थी। इस वैश्विक व्यवस्था का केंद्रबिन्दु भारत था, यह भी इतिहास से साबित होता है। पिछले कुछ सौ वर्षों से वैश्विक व्यवस्था का केंद्रबिंदु भारत से खिसक कर यूरोप की ओर चला गया, और मात्र इन कुछ सौ वर्षों में ही विश्व ने न केवल दो महायुद्ध, और 25-30 करोड़ लोगों का नरसंहार देख लिया, बल्कि प्रकृति तथा पर्यावरण का सत्यानाश हो गया और विश्व विनाश की कगार पर पहुँच गया। स्पष्ट है कि सभ्य और सभ्यता की परिभाषा और स्थापना में गड़बड़ी से ही यह सब विनाश हुआ और हो रहा है। इसलिए आज भी सभ्यताओं के संघर्ष के सिद्धांत गढ़े जा रहे हैं, अनिवार्य संघर्ष की स्थापनाएं दी जा रही हैं। इस विषम परिस्थिति में हर भारतीय का प्रयास होना चाहिए कि अपनी संस्कृति को भगवान राम की राह को तलाशने का। दुनिया की राजनीति, इतिहास और दर्शन को मौलिक संदर्भों और स्रोतों में भगवान राम के आदर्शों की पूर्ण रूप से प्रकाशित की है जरुरत है उसे समझने का। वर्तमान समस्याओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझने और उनका समाधान तलाशने व भारत माता के प्रति निस्वार्थ भाव से एक धरतीपुत्र का जिम्मेदारी को निभाने का आदर्श होना चाहिए जो सदियों से चलता आ रहा है जिसने मुगलों को टक्कर दि अंग्रेजो से भारत को आजाद कराया । पिछले कई सौ वर्षों में विश्व परिदृश्य में यूरोपीय देशों और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता के उभार ने पूरे विश्व के इतिहास और दर्शन को प्रभावित किया है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यूरोप के लोग केवल कुछ सौ वर्ष पहले तक शेष दुनिया से लगभग अनभिज्ञ थे।

यह लेखक के अपने विचार

गांधी के चंपारण में फिर उठा जमीन का प्रश्न

भारतीय लोकतंत्र और किसान आंदोलनों के इतिहास में केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक है। यही वह धरती है जहाँ 1917 में महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध शुरू हुआ वह आंदोलन केवल आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष नहीं था, बल्कि राज्य, समाज और नागरिक के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक क्षण भी था। गांधी ने चंपारण में यह स्थापित किया कि विकास या शासन का कोई भी मॉडल जनता की सहमति, न्याय और मानवीय गरिमा की उपेक्षा करके सफल नहीं हो सकता।

एक सदी से अधिक समय बाद पूर्वी चंपारण का पिपराकोठी क्षेत्र फिर भूमि के प्रश्न को लेकर चर्चा में है। इस बार विवाद नील की खेती का नहीं, बल्कि प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना का है। प्रशासन द्वारा वाटगंज क्षेत्र की लगभग 17 एकड़ भूमि को सरकारी घोषित कर उसकी जमाबंदी रद्द किए जाने के बाद किसान आंदोलनरत हैं। किसानों का कहना है कि वे और उनके पूर्वज पिछले सात-आठ दशकों से इस भूमि पर खेती करते आए हैं। उनके पास दाखिल-खारिज, राजस्व रसीदें तथा अतीत में मुआवजा मिलने जैसे दस्तावेज भी हैं। उनका आरोप है कि अचानक भूमि को सरकारी घोषित कर उनसे उनकी आजीविका का आधार छीनने की कोशिश की जा रही है।

दूसरी ओर प्रशासन की कार्रवाई इस आधार पर बताई जा रही है कि संबंधित भूमि सरकारी अभिलेखों में सरकारी संपत्ति है और प्रस्तावित विकास परियोजना के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई गई है। यही वह बिंदु है जहाँ विवाद का समाधान केवल राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि तथ्य, कानून और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया से ही संभव हो सकता है।

भूमि केवल संपत्ति नहीं होती; वह किसान के लिए उसकी पहचान, सुरक्षा और पीढ़ियों की स्मृतियों का आधार होती है। जिस खेत में एक परिवार कई दशकों तक खेती करता है, वह उसके लिए केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि जीवन का केंद्र बन जाता है। ऐसे में यदि भूमि की स्थिति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है।

एक साथ पांच राज्यो के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा!

राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा हाल ही में यह दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश,राजस्थान,छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश व बिहार में मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी कर रही है।अखिलेश यादव का आरोप है कि केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए एक बहाना ढूंढ रहा है, ताकि अंतत: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया जा सके।वही बिहार में भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है।साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यापक बदलाव करते हुए करीब 10 मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। इतना ही नही देश के पांच राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की भी संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि दो केंद्रीय मंत्रियों को राज्यपाल बनाया जा सकता है।

इन अटकलों को उस समय और बल मिला जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हालांकि, इस मुलाकात के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रपति भवन या गृह मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।फिर भी मध्य प्रदेश, राजस्थान ,उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक चर्चाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पार्टी या सरकार की ओर से ऐसी किसी संभावना की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है।

महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं, जबकि भाजपा संगठन में भी नई नियुक्तियों और जिम्मेदारियों को लेकर मंथन चल रहा है। फिलहाल यह पूरा घटनाक्रम राजनीतिक चर्चाओं और सूत्रों पर आधारित है। केंद्र सरकार और भाजपा की ओर से किसी भी बड़े फेरबदल को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सभी की नजरें आने वाले दिनों में पार्टी और सरकार के संभावित फैसलों पर टिकी हैं।लेकिन इन चर्चाओं को बल क्यो मिला ,इसके भी अलग अलग कारण सामने आ रहे है।

उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में दान-चढ़ावे की चोरी के आरोपों को लेकर राजनीति गरमा गई है। इस मुद्दे का इस्तेमाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने और उन्हें घेरने की कोशिश के रूप में हो रहा है।योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक विरोधी इस अवसर को भुनाने की फिराक में है और इस मुद्दे पर योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी कर रहे है।तभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोधियों ने इस विषय को राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है।योगी विरोधियों को लगता है कि योगी को कुर्सी से हटाने के इससे बेहतर अवसर कोई दूसरा नही हो सकता।लेकिन वास्तव में श्रीराम मंदिर में चंदा चोरी मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिला पाती है या नही यह आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा।

इसी प्रकार मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को उनके पद से हटाने का मुद्दा हाल ही में उनके और उनके परिवार द्वारा उज्जैन में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने से जुड़े जमीन सौदे के आरोपों के कारण गरमाया है।मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोहन यादव के परिवार और रियल एस्टेट फर्मों ने उज्जैन में भारी मात्रा में जमीन खरीदी है।

जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि उनके मंत्री और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार की जमीन का स्वामित्व लगभग 100 एकड़ से बढ़कर 335 एकड़ कैसे हो गया?यह जांच का विषय है।आरोप ये भी है कि ये जमीनें ज्यादातर उन क्षेत्रों में खरीदी गईं, जहां सरकार ने जमीन खरीदने के बाद नई सड़क परियोजनाओं और भूमि-उपयोग में बदलाव की घोषणा की थी।मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने इसे महाकाल की जमीन की लूट करार दिया है। कांग्रेस ने नैतिक आधार पर सीएम के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग की है।जबकि भाजपा का कहना है कि मोहन यादव का परिवार सालों से रियल एस्टेट के कारोबार में है और परिवार के निजी व्यापार को सीएम पद से जोड़ना गलत है।वही राजस्थान में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने हाल ही में दावा किया कि राजस्थान और दिल्ली दोनों स्तरों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पद से हटाने के लिए एक बड़ी साजिश चल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ऐसे दावे किए है कि भाजपा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदलने की तैयारी में है।कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि स्थानीय भाजपा विधायकों और नेताओं को दरकिनार किए जाने, और प्रशासन में नौकरशाहों का हस्तक्षेप अधिक होने से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति असंतोष पनप रहा है।गहलोत ने दावा किया है कि शर्मा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर ही एक भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा है.

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, अभी तो इनके खिलाफ में इनके पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी ,भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का, ये समझ नहीं पा रहे हैं. गहलोत ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद शर्मा के हित में यह सलाह दी है कि उन्हें बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एक युवा नेता को पहली बार मौका मिला है और वह सीधे मुख्यमंत्री बन गए हैं, यह बहुत बड़ी बात है।

चचाई थाना प्रभारी फूलमती अहिरवार ने संभाली कमान, असामाजिक तत्वों को दी सख्त चेतावनी

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक द्वारा चचाई थाना की नई थाना प्रभारी के रूप में नियुक्त की गई श्रीमती फूलमती अहिरवार ने पदभार ग्रहण करते ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चचाई थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, अपराध या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

थाना प्रभारी फूलमती अहिरवार ने क्षेत्र के लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति की शराब, जुआ, सट्टा, अवैध रेत उत्खनन, अवैध कोयला कारोबार या अन्य किसी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्तता पाई गई तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों से पुलिस का सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध या अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल चचाई थाना पुलिस को देने की अपील की है, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रहे और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके

केन्द्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों के बीच लंबित भुगतान निपटारे का समझौता हुआ

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हुआ।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीच नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबित भुगतान के निपटारे पर ऐतिहासिक समझौता हो गया है।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक में केन्द्र एवं चारों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यह समझौता मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के लागत साझाकरण के मुद्दों से जुड़े दीर्घकालिक विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसके तहत लंबित देयों के अंतिम निपटान के रूप में किए जाने वाले भुगतानों को एकमुश्त निपटान (वन-टाइम सेटलमेंट) के रूप में हल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से नर्मदा अवॉर्ड के लंबित भुगतान का विवाद चल रहा था, जिसका आज सौहार्दपूर्ण समाधान निकल गया है। अमित शाह ने कहा कि जल सुरक्षा को मजबूत करने और जल क्षेत्र में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कई ऐतिहासिक पहल की गई हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने इस महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय परियोजना पर आम सहमति बनाने में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा दिए गए रचनात्मक सहयोग की सराहना की। इस परियोजना से विशेषकर मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। बांध पूरा होने से इन राज्यों में हर जगह पानी और बिजली पहुंची। उन्होंने कहा कि राजस्थान को हुआ लाभ दिखने में छोटा लग सकता है, पर जिस भूमि तक नर्मदा का पानी पहुंचा है, वहां भूमि का मूल्य और किसान की किस्मत दोनों बदल गई है। गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल जी के नेतृत्व में देश में चल रहे जल विवाद या जल वितरण से जुड़े विवाद एक-एक कर सुलझाए जा रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा और राजस्थान के बीच का जल विवाद सुलझाया गया। चाहे किशाऊ बांध परियोजना का मुद्दा हो या राजस्थान, हरियाणा के बीच जल विवाद हो या आज का यह समझौता, ये सभी सहकारी संघवाद के स्वर्णिम उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या महाराष्ट्र, पानी देश के लोगों, खासकर किसानों के ही काम आता है। पानी का उपयोग चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो उससे लाभान्वित होने वाला एक भारतीय ही होगा । किसी भी विवाद से होने वाले राष्ट्रीय नुकसान को ध्यान में रख कर उसे सुलझाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पड़ोसी राज्य समृद्ध होता है, तो उसका लाभ अपने राज्य को भी मिलता है।

पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित पाँचवीं में अस्सी प्रतिशत व आठवीं में चोहत्तर प्रतिशत से अधिक उत्तीर्ण

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को कक्षा 5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी व अभिभावक राज्य शिक्षा केन्द्र के परीक्षा पोर्टल पर परिणाम देख सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की पुनः परीक्षा में कक्षा 5वीं में 80.42 एवं कक्षा 8वीं में 74.16 त्न परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं, मुख्य वार्षिक परीक्षा और पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को मिलाकर इस सत्र में कक्षा 5वीं का कुल परीक्षा परिणाम 98.89 एवं कक्षा 8वीं का कुल परीक्षा परिणाम 98.19 प्रतिशत रहा है।राज्य शिक्षा केन्द्र के अपर संचालक डॉ. अरूण सिंह ने बताया कि विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षकगण उक्त परिणामों को राज्य शिक्षा केन्द्र के https://www.rskmp.in/result.asp & पर अपना रोल नम्बर डालकर देख सकते हैं। साथ ही शिक्षक, संस्था प्रमुख भी अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम इसी पोर्टल पर देख सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 16 से 23 जून के बीच कक्षा 5वीं व 8वीं की पुनः परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश की शासकीय, अशासकीय शालाओं एवं पंजीकृत मदरसों के कक्षा 5वीं के 71, 548 तथा कक्षा 8वीं के 76, 274 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश में कुल 322 केन्द्र बनाए गए थे। 17, 000 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि पोर्टल पर दर्ज की गई थी।वहीं कक्षा पांचवीं में शासकीय स्कूलों के कुल 46, 665 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 36, 217 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मदरसा में 581 में से 352 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो वहीं अशासकीय स्कूलों के 24, 302 विद्यार्थियों में से 20, 971 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। इसी प्रकार कक्षा 8वीं में शासकीय स्कूलों के कुल 56,738 विद्यार्थियों में से 40, 315 उत्तीर्ण हुए हैं। मदरसा के 423 में से 268 और अशासकीय विद्यालयों के 19, 113 में से 15,978 विद्यार्थी पास हुए हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बड़ी सौगात सतगढ़ी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेन्टर

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भोपाल को सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और कन्वेंशन सेंटर की बड़ी सौगात मिली है। यह इंडस्ट्रियल पार्क देश के पहले उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सतगढ़ी क्षेत्र औद्योगिक विकास की दिशा में एक मंदिर के समान होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। प्रदेश में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र हमारे किसानों के लिए भी समृद्धि का द्वार खोलेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा। गारमेंट इंडस्ट्री से कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार खेत से कारखाने और उद्योग को बाजार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सोमवार को भोपाल के कोलार क्षेत्र स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र का भूमिपूजन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने %एक देश - एक विधान - एक निशान - एक प्रधान% की बात कही थी। समाज के हर वर्ग के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क से राजाभोज विमानतल की दूरी महज 25 किलोमीटर है। रानी कमलापति स्टेशन भी मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल का वेस्टर्न बायपास भी यहीं से गुजरेगा। सतगढ़ी के 25 एकड़ क्षेत्र में 10 हजार क्षमता वाला एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। मध्यप्रदेश अपने औद्योगिक विकास और पारदर्शी व्यवस्था के साथ तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। सागर ग्रुप के सुधीर अग्रवाल सतगढ़ी में 100 करोड़ का निवेश करेंगे। भोपाल प्राकृतिक सुंदरता और झील-तालाबों की नगरी है, लेकिन अब यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भी राजधानी की पहचान बनेगा। रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

एक ही आसन पर अमर हुए साहब

बिरसिंहपुर पावर हाउस में दशकीय साम्राज्य पर उठे सवाल!

उमरिया।

कहते हैं कि सरकारी नौकरी में तबादला एक ऐसी संजीवनी है जो व्यवस्था को सडऩे से बचाती है। लेकिन मध्यप्रदेश के सबसे बड़े बिजली घरों में से एक, संजय गांधी ताप विद्युत गृह (बिरसिंहपुर) की यूनिट क्रमांक 3 और 4 में नियम-कायदों का पावर कट हो चुका है। यहां एक ही परम प्रतापी साहब पिछले एक दशक (10 साल) से अपनी कुर्सी पर फेविकोल का ऐसा मजबूत जोड़ लगाकर बैठे हैं कि बड़े-बड़े प्रशासनिक आदेश भी उन्हें डिगा नहीं पाए। परियोजना के गलियारों से लेकर उमरिया के पान के ठेलों तक, अब यह कौतूहल का विषय बन चुका है कि आखिर साहब की इस अटूट कुर्सी भक्ति का राज क्या है?

प्रमोशन पाया, पर मोहल्ला नहीं बदला!

प्रशासनिक नियमावली चिल्ला-चिल्ला कर कहती है कि संवेदनशील पदों पर बैठे अधिकारियों का समय-समय पर ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बची रहे। लेकिन यहाँ तो सुशासन की धज्जियां उड़ रही हैं। सूत्रों की मानें तो इन महाशय ने इसी यूनिट की छांव में रहते हुए पदोन्नति (प्रमोशन) के मीठे फल भी चख लिए, लेकिन मजाल है कि उनका कार्यक्षेत्र बदला हो! पद बदल गया, रुतबा बढ़ गया, लेकिन यूनिट नंबर 3 और 4 से उनका जनम-जनम का नाता अटूट रहा। बिजली घर के कर्मचारियों के बीच अब यह आम धारणा बन चुकी है कि जब एक ही संवेदनशील पद पर कोई लंबे समय तक अंगद की तरह पैर जमा लेता है, तो वहाँ उसका अपना एक समानांतर साम्राज्य खड़ा हो जाता है।

सुशासन का फ्यूज उड़ा, अब प्रबंधन पर टिकीं निगाहें

क्या संजय गांधी ताप विद्युत गृह का प्रबंधन इस दशकीय साम्राज्य से अनजान है या फिर ऊपर से नीचे तक सब ऑल इज वेल के सुर में सुर मिला रहे हैं? सुशासन का तकाजा तो यही कहता है कि हर संवेदनशील पद की समीक्षा हो। अगर साहब पूरी तरह पाक-साफ हैं, तो वे जांच से क्यों कतराएंगे? एक निष्पक्ष जांच ही उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे सकती है। अब देखना यह है कि बिरसिंहपुर का यह शीर्ष प्रबंधन इस गंभीर मामले पर अपनी आंखें खोलता है या फिर धृतराष्ट्र बनकर कुर्सी के इस तमाशे को देखता रहता है। क्षेत्र की जनता की निगाहें अब प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह संस्थान की साख बचाता है या फिर इस दशकीय मोह को और पल्लवित होने देता है।

ठेका, मेंटेनेंस और आर्थिक चमत्कार की चर्चाएं

जब बिजली के तारों से ज्यादा साहब के रसूख में करंट आ जाए, तो सवाल उठना लाजिमी है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पिछले कुछ वर्षों में यूनिट के भीतर जितने भी तकनीकी और मेंटेनेंस के काम हुए, उनकी गुणवत्ता भगवान भरोसे थी। ठेका आवंटन की प्रक्रियाओं में ऐसी जादूगरी दिखाई गई कि जानकार भी उंगलियां दबा लें, हालांकि, समाचार पत्र स्वतंत्र रूप से इन आरोपों पर मुहर नहीं लगाता, लेकिन जनता की जुबान पर लगे तालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तो क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने सीधे-सीधे साहब के आर्थिक चमत्कार पर उंगली उठा दी है। मांग तेज हो रही है कि पिछले 5 वर्षों में साहब की संपत्ति में जो रोशनदान खुला है और जितनी तेजी से लक्ष्मी जी ने उनके घर पर अपनी कृपा बरसाई है, उसके स्रोतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

जामुडोलः भवन विहीन आंगनबाड़ी का आदेश बना सिरदर्द, एक कमरे में कैसे बैठेंगे मासूम?

भैंसदेही

सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस कोड साड़ी अनिवार्य कर दिया है, लेकिन पलासपानी पंचायत के जामुडोल गांव में आंगनबाड़ी का अपना भवन ही नहीं है। नए आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 1 किमी के दायरे में जहां भवन नहीं है या क्षतिग्रस्त है, वहां आंगनबाड़ी को सरकारी स्कूल में शिफ्ट करना है। अब सवाल यह है कि जहां स्कूल के पास जगह ही नहीं, वहां मासूम बच्चे कैसे बैठेंगे?

एक कमरे में चल रहा पूरा स्कूल, बच्चे बरामदे में मजबूर

जामुडोल की प्राथमिक शाला में नाम मात्र का एक ही कमरा है। उसी एक कमरे में कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चे पढ़ते हैं। जगह के अभाव में 12 महीने बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बरामदा ही एकमात्र सहारा है, और वह भी मानसून में पूरी तरह खुला रहता है।

बारिश में आंगनबाड़ी के बच्चों का क्या होगा?

ऐसी स्थिति में शासन के शिफ्टिंग आदेश पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब स्कूल के अपने बच्चे ही भारी बारिश में बरामदे में भीगने को मजबूर हैं, तो आंगनबाड़ी के 3 से 6 साल के मासूम कहां और कैसे बैठेंगे? अभिभावकों और कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर है।

1 बजे छुट्टी, कार्यकर्ता-सहायिका घर में विश्राम

जगह और भवन की कमी के कारण यहां आंगनबाड़ी समय पर संचालित नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि 1 बजे ही आंगनबाड़ी के बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। इसके बाद कार्यकर्ता और सहायिका दोनों घर में विश्राम कर रही हैं।

भवन निर्माण और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रेस कोड से पहले बुनियादी ढांचा जरूरी है। जामुडोल में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण शीघ्र कराया जाए, या तब तक बच्चों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बारिश के मौसम में खुले बरामदे में छोटे बच्चों को बैठाना किसी भी तरह से उचित नहीं है।

इनका क्या कहना,,,,,

भवन न होने के कारण प्राथमिक शाला में लगाई जा रही है आंगनवाड़ी ,शासन को प्रस्ताव बना कर भेज दिया है

सुनीता शैलू प्रभारी महिला बाल विकास

टीन शेड हटाने का विरोधः व्यापारियों ने तहसीलदार और सीएमओ को सौंपा ज्ञापन

बारिश में रोजी-रोटी पर संकट, कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग

सुठालिया।

नगर परिषद द्वारा नगर में हाथ ठेलों और दुकानों के सामने लगे टीन शेड हटाने की कार्रवाई के विरोध में शनिवार को व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। समस्त व्यापारी, हाथ ठेला संचालक और नगरवासियों ने तहसीलदार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्षा ऋतु को देखते हुए छोटे व्यापारियों और ठेला संचालकों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। बारिश में सामान और खुद को बचाने के लिए लगे अस्थायी शेड जरूरी हैं। ऐसे में कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए और व्यापारियों के हित में कोई उचित समाधान निकाला जाए। व्यापारियों ने भरोसा जताया कि नगर परिषद जनहित और व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी। ज्ञापन देने वालों में नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मिथुन सिलावट और पार्षद मोहसिन खान रांझा प्रमुख रूप से शामिल रहे।

बस स्टैंड पर मारपीट, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

सुठालिया।

बस स्टैंड पर फल की कैरेट को लेकर हुए विवाद में मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपी अभी फरार हैं। 5 जुलाई की शाम करीब 6.10 बजे सेलिब्रेशन गार्डन रोड निवासी बबलू केवट, मनीष केवट और जगदीश उर्फ चिंटू ने भोजपुरिया निवासी योगेश तोमर 28 से विवाद किया। आरोप है कि तीनों ने गाली-गलौज कर डंडे और पाइप से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सुठालिया में अपराध क्रमांक 274/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार तोलानी के निर्देश पर एसडीओपी प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अनिल राहोरिया की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बबलू केवट को बस स्टैंड से पकड़ लिया। उस पर बीएनएसएस के तहत प्रकरण बनाकर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है। कार्रवाई में सउनि अशोक कटारिया, प्रआर विनोद कुमार, आरक्षक राधारमण और आरक्षक शुभम शामिल रहे।

भाजपा का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न

कार्यकर्ता डॉ मुख़र्जी के विचारों को आत्म साथ कर अपनी जिम्मेवारी का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करें:गौरव

उमरिया।

भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोमवार को भाजपा कार्यालय भरौली में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के तहत जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमे संभागीय संगठन प्रभारी गौरव सिरोठिया, जिला प्रभारी राजेन्द्र पाण्डेय, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल, विधायक मानपुर, बांधवगढ़ विधायक , जिला पंचायत अध्यक्ष,वरिष्ठ नेता मिथलेश पयासी ,राकेश शर्मा,महामंत्री हरीश विश्वकर्मा, राधेलाल कोल मंचासीन रहे। जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए संभागीय संगठन प्रभारी गौरव सिरोठिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा और कार्यकर्ता आधारित, अनुशासित संगठन है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके संस्कार, विचार, कार्यपद्धति और समर्पित कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसे राजनीतिक दल की कल्पना की थी, जो केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद, संगठन, संस्कार और विचारधारा पर आधारित हो। उन्होंने जिला सम्मेलन में आए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाते हुए कहा कि कार्यकर्ता डॉ मुख़र्जी के विचारों को लेकर आगे बढ़े और संगठन के द्वारा जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौपी गई है वह उसे निष्ठा पूर्वक निर्वहन करे।

भाजपा के लिए बूथ केवल मतदान केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की इकाई है:आशुतोष

भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल ने कहा कि भाजपा के लिए बूथ केवल मतदान केंद्र नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की इकाई है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रहित, विचारधारा और संगठन को सर्वोपरि मानकर कार्य करता है। भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी उसका समर्पित कार्यकर्ता है, जिसने अपने अथक परिश्रम और निष्ठा से पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि, विचारधारा सर्वोपरि और संगठन सर्वोपरि के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करें।

नेहरू द्वारा जम्मू-कश्मीर में धारा 370 लगाने का दंश देश ने वर्षों तक सहा:शिवनारायण

बांधवगढ़ विधानसभा के विधायक शिवनारायण सिंह ने कहा कि देश के आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर को विशेष सुविधाएं दीं, वह देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई हैं। पंडित नेहरू द्वारा जम्मू-कश्मीर में धारा-370 लगाने का दंश देश ने वर्षों तक सहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर देश के मुकुटमणि पर लगा कलंक मिटाने का कार्य किया है। वही अब भारत मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त और समृद्ध हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाकर राष्ट्र निर्माण के इस अभियान को और अधिक सशक्त बनाएं।जिला प्रभारी राजेंद्र पांडे ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दूरदर्शी राष्ट्रनायक थे, जिन्होंने देश के भविष्य की चुनौतियों को समय रहते पहचाना और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सांस्कृतिक अस्मिता के पक्ष में निर्भीकता से आवाज बुलंद की। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। उन्होंने ब्रिटिश शासन की विभाजनकारी नीतियों का विरोध किया तथा बंगाल के विभाजन सहित राष्ट्रविरोधी षड्यंत्रों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा-370 और 35ए को समाप्त कर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को साकार किया गया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर पूर्ण रूप से भारत की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा और राष्ट्र की एकता को नई मजबूती मिली।

आजादी के बाद देश की अखंडता के लिए पहला बलिदान डॉ. मुखर्जी ने दिया:मिथलेश

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिलेश पयासी ने कहा कि देश के आजाद होने के लिए लाखों की संख्या में लोगों ने बलिदान दिए, लेकिन देश के आजाद होने के बाद उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए पहला बलिदान देने वाले महापुरूष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद से डॉ. मुखर्जी ने इस्तीफा देने के कई कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा और पहला कारण था कि नेहरू सरकार बहुसंख्यक वर्ग की सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई ठोस कार्य नहीं कर रही थी। डॉ. मुखर्जी ने अपने इस्तीफे में इस बात का उल्लेख किया है कि देश के बंटवारे के दौरान नेहरू-लियाकत समझौता जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, उसका भारत तो पालन कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान पालन नहीं कर रहा था। डॉ. मुखर्जी इस बात से नाराज थे कि पंडित नेहरू बहुसंख्यक समाज की सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे थे, सिर्फ अल्पसंख्यकों के हितों के कार्यों में लगे थे। नेहरू द्वारा जम्मू-कश्मीर में धारा 370

तेंदूखेड़ा के मुख्य मार्ग खकरिया रोड पर जाम की समस्या से आमजन परेशान, नागरिकों ने व्यवस्था सुधार की मांग की

तेंदूखेड़ा

नगर के मुख्य मार्ग से खकरिया मार्ग पर प्रतिदिन लगने वाले लगातार जाम के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ स्कूल, कॉलेज एवं विभिन्न शासकीय कार्यालयों में आने-जाने वाले लोगों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार इस मार्ग पर कई दुकानदारों द्वारा सामान को दुकानों से बाहर सड़क तक फैला दिया जाता है, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और आवागमन बाधित होता है। इसी कारण दिनभर में कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे मरीजों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं आम राहगीरों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत होती है। नागरिकों ने बताया कि यह मार्ग नगर का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि इसी रास्ते से शैक्षणिक संस्थानों, महाविद्यालयों एवं विभिन्न विभागीय कार्यालयों का आवागमन होता है।

राष्ट्रीय युवा संसद में दमोह के निखिल सोनी ने किया मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व, प्रभावशाली वक्तव्य से बटोरी सराहना

तेंदूखेड़ा

राजस्थान विधानसभा, जयपुर में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय युवा संसदङ्क2026 में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए दमोह जिले के तेंदूखेड़ा निवासी निखिल सोनी ने अपने प्रभावशाली वक्तव्य से सभी का ध्यान आकर्षित किया। महिला आरक्षण, चुनावी पारदर्शिता एवं विकसित भारतङ्क2047 जैसे समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर उन्होंने तार्किक, संतुलित एवं तथ्यपरक विचार प्रस्तुत किए, जिनकी सदन में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों ने सराहना की। अपने संबोधन में निखिल सोनी ने कहा कि महिला आरक्षण केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि समान अवसर, सामाजिक न्याय और सशक्त भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया, नीति निर्माण और नेतृत्व के अवसरों में समान भागीदारी सुनिश्चित किए बिना विकसित भारत की परिकल्पना पूर्ण नहीं हो सकती। चुनावी पारदर्शिता पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग, मतदाता जागरूकता, राजनीतिक दलों की जवाबदेही तथा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी चुनाव ही मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान हैं। विकसित भारतङ्क2047 के विषय पर निखिल सोनी ने कहा कि यह केवल सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन एक खुली किताब की तरह, उनके विचार आज भी राष्ट्र को दिशा दे रहे हैं : नारायण चंदेल

सक्ती

भारतीय जनता पार्टी जिला सक्ती द्वारा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री टिकेश्वर सिंह गबेल की अध्यक्षता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल के मुख्य आतिथ्य तथा पूर्व मंत्री श्री मेघाराम साहू, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री रामावतार अग्रवाल, प्रदेश मंत्री श्रीमती विद्या सिदार, पूर्व विधायक डॉ. खिलावन साहू, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री श्री सम्पूर्णानंद मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी कीर्तन चंद्रा एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री गगन जयपुरिया के विशिष्ट आतिथ्य में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद्, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं अखंड भारत के प्रबल समर्थक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती श्रद्धा, सम्मान एवं राष्ट्रभक्ति के वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। मुख्य वक्ता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिससे प्रत्येक भारतीय राष्ट्रभक्ति, त्याग, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा ले सकता है। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी की सोच सदैव एक सशक्त, समृद्ध और अखंड भारत के निर्माण की रही। वे देश में एकता, अखंडता और सांस्कृतिक गौरव को सर्वोच्च मानते थे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें का भाव उनके जीवन का मूल मंत्र था। उन्होंने कश्मीर में लागू पृथक व्यवस्था का विरोध करते हुए राष्ट्र की एकता के लिए संघर्ष किया और राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि महापुरुष अपने विचारों और राष्ट्र के प्रति किए गए कार्यों के कारण सदैव अमर रहते हैं।अध्यक्षीय उद्बोधन में जिला भाजपा अध्यक्ष श्री टिकेश्वर सिंह गबेल ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, संगठन, त्याग और सेवा का अनुपम उदाहरण है। उनके विचार आज भी प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता डॉ. मुखर्जी के आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाने तथा उनके बताए मार्ग पर चलकर राष्ट्रहित और समाजसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है।पूर्व मंत्री श्री मेघाराम साहू ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्रहित को सदैव सर्वोपरि रखा। उनका व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त प्रतीक था। उनके विचारों को आत्मसात कर ही भारत को और अधिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। मनचस्थ अतिथियों ने भी डॉ श्यामा प्रसाद जी के जीवन आदर्शों पर अपने विचार व्यक्त किए।इस अवसर पर शासन द्वारा मनोनीत नगरपालिकाओं के नवनियुक्त एल्डरमैनों का स्वागत एवं सम्मान किया

महिलाओं और बच्चों की डिजिटल और साइबर सुरक्षा के लिए एनजीओ, महिला आयोग और गूगल एक मंच पर

इंदौर

इंदौर, 09 जुलाई 2026 डिजिटल तकनीक के तेजी से बढ़ते उपयोग के साथ महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा आज देश के सामने सबसे बड़ी सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों में शामिल हो गई है। इसी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, आहान फाउंडेशन और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल के सहयोग से भोपाल में आयोजित विशेष एनजीओ मीट में डिजिटल सुरक्षा , साइबर अपराधों की रोकथाम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग पर व्यापक विमर्श हुआ। मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की सदस्य श्रीमती साधना स्थापक ने कहा कि डिजिटल युग ने जितने अवसर उपलब्ध कराए हैं, उतनी ही नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा केवल कानून या तकनीक का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की बदलती प्रकृति को देखते हुए डिजिटल जागरूकता, समय पर शिकायत और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार को जन-आंदोलन का स्वरूप देना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित उपयोग सिखाना समय की आवश्यकता है। परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों और शासन के समन्वित प्रयासों से ही ऐसा डिजिटल वातावरण बनाया जा सकता है, जहां प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव श्री सुरेश तोमर भी उपस्थित रहे। 'रिस्पॉन्सिबल नेटिजन' कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित संवाद में महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भाग लेकर जमीनी अनुभव साझा किए तथा डिजिटल सुरक्षा को लेकर सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में गूगल की डायरेक्टर (सर्च एंड जेनरेटिव एआई ट्रस्ट एंड सेफ्टी) सुश्री स्निग्धा भारद्वाज ने 'चाइल्ड सेफ्टी एंड एआई' विषय पर कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास बच्चों और समाज के हितों को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जोखिमों की पहचान और बच्चों के लिए जिम्मेदार डिजिटल वातावरण तैयार करने की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं गूगल के ट्रस्ट एंड सेफ्टी विभाग के श्री समीर ने साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं और सुरक्षा मानकों की जानकारी साझा की। आहान फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री सोनाली पाटणकर ने डिजिटल सुरक्षा पर आयोजित विशेष सत्र में साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न, फर्जी लिंक, डेटा सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग से जुड़े व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी।

ग्राम पंचायत छातेर में साइबर अपराध से बचाव पर कार्यशाला आयोजित

हल्केवीर सूर्यवंशी, संभागीय संवाददाता

उदयपुरा/रायसेन। ग्राम पंचायत छातेर के पंचायत भवन में रविवार को साइबर अपराध से बचाव एवं ऑनलाइन सुरक्षा विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में थाना प्रभारी जयवंत सिंह ककोड़िया ने ग्रामीणों को साइबर ठगी के नए तरीकों की जानकारी देते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाता, ओटीपी, एटीएम पिन या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें तथा संदिग्ध कॉल या लिंक से सतर्क रहें।

कार्यशाला में सरपंच प्रतिनिधि हरिशंकर गुर्जर, उपसरपंच रामकृष्ण पाल, सचिव रमन वामने सहित जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक कर सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

डायल-112 की तत्परता से भटके 8 वर्षीय बालक को सुरक्षित परिजनों से मिलाया

हल्केवीर सूर्यवंशी, संभागीय संवाददाता

मंडीदीप। कलियासोत ब्रिज के पास भटका हुआ 8 वर्षीय पीयूष लोधी डायल-112 टीम को मिला। सूचना मिलते ही इवेंट क्रमांक 06072602589 पर तैनात एस.के. लक्ष्मण एवं पायलट हेमंत अहिरवार मौके पर पहुंचे और बालक से पूछताछ कर उसके बताए पते आकृति इको सिटी, विदिशा रोड, भोपाल की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद डायल-112 टीम ने तत्परता दिखाते हुए बालक को सुरक्षित उसके नाना-नानी के सुपुर्द कर दिया।

परिजनों ने पुलिस की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया।

हमारे प्रिये भाई, बहुत ही मिलनसार, व्यक्ति त्व के धनी युवा प्रदेश की आन बान सान और युवा प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन हेड बृजेन्द्र मांडरे जी को जन्म दिन की बहुत बहुत बधाई युवा प्रदेश न्यूज़ ग्रुप की ओर से । हम आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं और आपके जीवन मे ढेर सारी तरक्की आए

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड, तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक** : नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)